B - 3 & 4
L - 31
Social Justice

राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक (NMPI) :

- इसको नीति आयोग द्वारा वैश्विक मल्टीडायमेंशनल पॉवर्टी इन्डैक्स (ग्लोबल NPI) की तर्ज पर शुरू किया गया है।

इसमें भारत में NPI के समान महत्व वाले 9 आयाम हैं जिसके आधार पर Indian-NPI का मापन किया जाता है ये तीन आधार हैं-

(i) स्वास्थ्य
(ii) शिक्षा
(iii) जीवन स्तर

जो बारह संकेतकों द्वारा दर्शाये जाते हैं।

↓

- India-NPI को - Head Count अनुपात (H) और निर्धनता की तीव्रता (A) को गुणा करके निकाला जाता है। **H x A**

यह गरीबी में लोगों की हिस्सेदारी तथा उनके वंचित होने की स्थिति को, दोनों को दर्शाता है।

KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

Scanned by CamScanner

भूख और भुखमरी का अर्थ :-

- World Food Programme के अनुसार- 'भूख (Hunger) भूखे होने की भावना है जबकि भुखमरी (Starvation) :-

शब्द का इस्तेमाल अक्सर ऐसे व्यक्तियों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिसने एक लम्बे समय से बहुत कम या बिलकुल भी भोजन न किया हो।

WHO के अनुसार- भुखमरी में खाने की कमी के साथ-साथ खाना की गुणवत्ता को भी इसमें शामिल किया है।

भारत में गरीबी एवं भुखमरी का स्वरूप :-

- भारत दुनियां का सर्वाधिक आबादी वाला देश है जहाँ गरीबी एवं भुखमरी की समस्या आज भी बनी हुई है।
- पिछले कुछ वर्षों में गरीबी की दर में उल्लेखनीय गिरावट आई है (NPI → 2013-14 के 29.17 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में 11.28 प्रतिशत, नीति आयोग रिपोर्ट 2024)

लेकिन भूख का स्तर अभी भी ऊँचा बना हुआ है।

Scanned by CamScanner

- वैश्विक भूख सूचकांकों में भी भारत का प्रदर्शन बहुत खराब है।
(2023 में 125 देशों में भारत का 111 वाँ स्थान – स्कोर - 28.7%, Global Hunger Index 2023)

और यह स्थिति दर्शाती है कि - आर्थिक विकास और गरीबी में कमी अकेले भूख एवं कुपोषण की समस्या का समाधान करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

भारत में गरीबी और भुखमरी के बीच अन्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और गरीबी की दर में कमी के बावजूद भुखमरी के स्तर में कमी नहीं आयी है।

↓

इसका एक प्रमुख कारण - सरकार द्वारा सामाजिक व्यय में कमी करना है जो गरीबों को गैर खाद्य आवश्यक वस्तुओं पर अधिक खर्च करने के लिए मजबूर करता है। जिससे उनका भोजन बजट कम हो जाता है।

KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

Scanned by CamScanner

नीति आयोग के अनुसार भारत में गरीबी

↓

PDF Notes

'UNDP' (United Nation Development programme) वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक-2023

↓

PDF Notes

भारत में भुखमरी का स्वरूप :

भारत इस समय दुनियाँ में सर्वाधिक आबादी वाला देश है परन्तु प्रति-व्यक्ति खाद्यान की उपलब्धता अमेरिका और चीन जैसे कई देशों की तुलना में कम है।

साथ ही कृषि पर अत्याधिक निर्भरता ने भुखमरी की समस्या को बनाये रखा है। और इसके लिए एक प्रमुख कारण है कृषि में निवेश की कमी और परम्परागत तरीके से खेती।

Global Hunger Index-2023 में भारत का प्रदर्शन :-

↓

PDF Notes

Scanned by CamScanner

भारत में गरीबी एवं भुखमरी के कारण :-

[A] गरीबी के प्रमुख कारण :-

(i) ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियाँ।
(ii) आय और परिसंपत्तियों के वितरण में असमानता।
(iii) सामाजिक सेवाओं तक पहुँच में असमानता।
(iv) संस्थागत ऋण तक पहुँच की कमी।
(v) उत्पादक रोजगार की कमी।
(vi) जाति व्यवस्था।
(vii) सामाजिक रीति-रिवाजों द्वारा गैर उत्पादक खर्च को बढ़ाना।
(viii) कृषि में कम उत्पादकता।
(ix) गरीबी का दुश्चक्र

[B] भारत में भुखमरी के प्रमुख कारण :

(i) गरीबी
(ii) लैंगिक असमानता
(iii) खराब शासन / भ्रष्टाचार
(iv) अज्ञात भूख या अज्ञात भुखमरी
  ↳ मार्क्सवादियों द्वारा → छुपे हुए गरीब
(v) मातृ ज्ञान की कमी।
(vi) प्राकृतिक आपदायें।
(vii) जलवायु परिवर्तन एवं संसाधनों का दुरुपयोग।

KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

Scanned by CamScanner

भारत सरकार द्वारा गरीबी एवं भुखमरी को रोकने हेतु किये गये संवैधानिक एवं वैधानिक प्रयास :-

↓

संवैधानिक एवं वैधानिक प्रयास :-

- संविधान की प्रस्तावना में आर्थिक न्याय की प्राप्ति पर बल।
- अनुच्छेद 19(g) - हर नागरिक को स्वतंत्रता पूर्वक अपना पेशा चुनने का अधिकार होगा ताकि वह गरीबी एवं भुखमरी से बच सके।
- अनुच्छेद 21 - जीवन की स्वतंत्रता के अधिकार में गरीबी एवं भुखमरी का उन्मूलन भी शामिल है।
- अनुच्छेद 38 - राज्य को सामाजिक एवं राजनीतिक न्याय के साथ आर्थिक न्याय को बढ़ावा देना।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

↓

PDF Notes

KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

Scanned by CamScanner

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013

- यह अधिनियम देश के नागरिकों को भोजन का कानूनी अधिकार प्रदान करता है जिसके उद्देश्यों में देश के 145 करोड़ लोगों में से लगभग दो तिहाई लोगों को (ग्रामीण क्षेत्रों में 75% तथा शहरी क्षेत्रों में 50%) सब्सिडी वाले खाद्यान उपलब्ध करना है।

(चावल - 3₹/Kg ; गेहूँ - 2₹/Kg ;
मोटा अनाज - 1₹/Kg और कुल प्रतिव्यक्ति 35 Kg प्रतिमाह - उपलब्ध कराया जाता है।)

भारत सरकार द्वारा गरीबी उन्मूलन हेतु किये गये नीतिगत योजनागत प्रयास -

KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

Scanned by CamScanner